भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *200
12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तपेदिक मुक्त भारत

***200. श्री भर्तृहरि महताबः**
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा राज्य सहित देश में पिछले एक दशक के दौरान तपेदिक रोग की घटनाओं, मृत्यु दर और उपचार कवरेज में देखे गए रुझानों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तपेदिक रोग की रोकथाम, इसका शीघ्र पता लगाने और इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए तपेदिक रोग (टीबी) मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अपनाई गई प्रमुख कार्यनीतियां क्या हैं;

(ग) हाल ही के रिपोर्ट वर्ष के दौरान तपेदिक रोग के कितने रोगियों की जांच की गई, रोग का पता लगाया गया और इसका उपचार किया गया;

(घ) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तपेदिक रोगियों को दी गई वित्तीय, पोषण और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है और राजस्थान राज्य, विशेषकर पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्या हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन और तपेदिक रोग की घटनाओं, मृत्यु दर और उपचार कवरेज का ब्यौरा क्या है; और

(च) मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त अभियान के क्या परिणाम निकले?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*200 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में टीबी के मामलों में 21% की गिरावट आई है, जो 2015 में प्रति लाख आबादी पर 237 से घटकर 2024 में 187 हो गई है। प्रति लाख आबादी पर टीबी से होने वाली मृत्यु दर प्रति लाख आबादी पर 2015 में 28 से घटकर 2024 में 21 हो गई, जोकि 25% की गिरावट दर्शाती है, और भारत में टीबी उपचार कवरेज 2015 में 53% से बढ़कर 2024 में 92% हो गया है।

टीबी मुक्त भारत अभियान (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम) देश के सभी राज्यों (ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत लागू किया जाता है।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रमुख कार्यनीतियों में लक्षणहीनता सहित जोखिमग्रस्त आबादी की पहचान, प्रारंभिक पहचान के लिए छाती के एक्स-रे द्वारा स्क्रीनिंग, सभी संभावित टीबी मामलों के लिए अग्रिम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी), समय पर उपचार की शुरुआत और पूर्ण उपचार, उच्च-जोखिम वाले टीबी मामलों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग टीबी परिचर्या तथा पात्र जोखिमग्रस्त आबादी को पोषण सहायता और निवारक उपचार शामिल हैं।

इस अभियान (दिनांक 07.12.24 से 09.12.25) के तहत, संवेदनशील आबादी की जांच के माध्यम से 26.43 लाख टीबी मामलों का निदान किया गया, जिसमें 9.19 लाख लक्षणरहित टीबी मामले शामिल हैं और जिन्हें उपचार में शामिल किया गया है।

नि-क्षय पोषण योजना के तहत उपचार की पूरी अवधि के लिए प्रत्येक रोगी को प्रति माह ₹1000 पोषण सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। पल्ली निर्वाचन क्षेत्र सहित, राजस्थान में अब तक 9.6 लाख टीबी रोगियों को ₹309 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, नि-क्षय मित्र पहल के तहत सहमति देने वाले 3.7 लाख टीबी रोगियों को फूड बास्केट्स प्रदान किए गए हैं।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान टीबी के 8,858 मामलों की पहचान की गई और उपचार के अंतर्गत लाए गए।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, मध्य प्रदेश के सिधी संसदीय क्षेत्र में आने वाले सिधी, सिंगरौली और शाहडोल जिलों में 8,400 नए टीबी मामलों की पहचान की गई, जिनमें 2,126 लक्षणरहित मामले शामिल हैं।

*****